मूल्य 1 रुपया

कृषक समाचार

भारत कृषक समाज का मासिक मुख पत्र

कृषक समाचार की 32,000 प्रतियां सन् 1960 से हर महीने छापकर सदस्यों को भेजी जाती हैं

वर्ष 67 | जुलाई, 2022 | अंक 07 | कुल पृष्ठ 8

सहकार से समृद्धिः रास्ते अनेक

--- हरवीर सिंह

(नोट: ये लेखक के अपने विचार है)

मीडिया संस्थान रूरल वॉयस ने सहकारिता पर एक परिचर्चा का आयोजन किया। इसका मकसद सहकारिता आंदोलन की अड़चनों को पहचानना और सहकारिता को आगे बढ़ाने के लिए नई संभावनाओं पर विचार करना था। परिचर्चा में सहकारिता क्षेत्र की कई जानी-मानी हस्तियों ने हिस्सा लिया।

परिचर्चा का विषय था ''सहकार से समृद्धिः रास्ते अनेक'' । इसमें में तीन सत्र रखे गए थे। पहले सत्र का विषय था बेहतर आय के लिए कोऑपरेटिव को मजबूत करना। दूसरे सत्र का विषय था सहकारिता में वैश्विक अनुभव का भारत कैसे फायदा उठाए। तीसरे और आखिरी सत्र का विषय था कोऑपरेटिव को कैसे प्रासंगिक बनाया जाए।

विशेषज्ञों ने परिचर्चा में सहकारी समितियों के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए कई महत्वपूर्ण सलाह, सुझाव दिए।

टेक्नोलॉजी से आएगी पारदर्शिता: सिराज हुसैन

'बेहतर आय के लिए कोऑपरेटिव को मजबूत करना' विषय पर पहले सत्र की शुरुआत करते हुए पूर्व कृषि सचिव सिराज हुसैन ने नए सहकारिता मंत्रालय के गठन को अच्छा कदम बताते हुए कहा कि इसे कोऑपरेटिव के कामकाज में पारदर्शिता लाने की दिशा में कदम उठाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि कोऑपरेटिव में टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इससे उनके काम में पारदर्शिता आएगी। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में सभी प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) का कंप्यूटराइजेशन हो गया है जबकि उत्तर प्रदेश में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर किसी कोऑपरेटिव में गड़बड़ी होती है तो टेक्नोलॉजी से उसका जल्दी पता लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि व्यापक चर्चा से ही बेहतर नीति बनेगी

पूर्व कृषि सचिव के अनुसार सरकार को सीधे कोऑपरेटिव को रेगुलेट नहीं करना

चाहिए वरना इससे तनाव बढ़ेगा। सरकार इन संस्थाओं को रेगुलेट तो करें लेकिन इस तरह कि सदस्यों को कोई नुकसान ना हो। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे कोऑपरेटिव का आकार बढ़ता जाता है उसकी वित्तीय शक्ति भी बढ़ती है। ऐसे में उन पर नियंत्रण के लिए लोगों में होड़ मचती है।

उन्होंने कहा कि बीते दो दशक में कोऑपरेटिव का असर कम हुआ है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में डेयरी कोऑपरेटिव का हिस्सा लगातार कम होता जा रहा है। कोऑपरेटिव में होने वाली खरीद सरकारी ई-कॉमर्स पोर्टल जैम के जरिए किए जाने के फैसले का उन्होंने स्वागत किया और कहा कि इससे पारदर्शिता आएगी।

किसानों को अधिक कीमत मिले और लागत कम हो: जयेन मेहता

अमूल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जयेन मेहता ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए जरूरी है कि उन्हें उनके उत्पाद की अधिक से अधिक कीमत मिले और उनकी लागत कम हो। अमूल इसी मॉडल पर काम करता है। भारत में डेयरी कोऑपरेटिव की संभावनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अभी दुनिया का 22 फ़ीसदी दूध उत्पादन भारत में होता है। 10 साल में यह 35 फ़ीसदी हो जाएगा। इन 10 वर्षों में जो अतिरिक्त दूध उत्पादन होगा उसका भी दो तिहाई भारत से आएगा। उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव किसानों की उत्पादकता बढ़ाने उनका खर्च घटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि अमूल उपभोक्ताओं से दूध की जो कीमत लेता है किसानों को उसका 85 फ़ीसदी मिलता है। अमूल की उपलब्धियां बताते हुए उन्होंने कहा कि करीब 36 लाख किसान इससे जुड़े हैं। कोई भी किसान इससे आसानी से जुड़ सकता है। इस संस्था का सालाना टर्नओवर 61 हजार करोड़ रुपए पहुंच गया है।

क्रेडिट कोऑपरेटिव को बीमा कवरेज मिले: डॉ उदय जोशी

सहकार भारती के राष्ट्रीय महासचिव डॉ उदय जोशी ने कोऑपरेटिव में सुधार को जरूरी बताते हुए कहा कि इनमें मलिन छवि की बात काफी समय से चलती आ रही है। पहले भी कहा गया है कि कोऑपरेटिव विफल हुए हैं लेकिन इन्हें सफल होना चाहिए। संविधान के 97वें संशोधन के बाद उसका ऑपरेशनल हिस्सा खारिज किया गया लेकिन यह बात खारिज नहीं हुई कि कोऑपरेटिव बनाना मौलिक अधिकार है। देश में 95000 से अधिक प्राथमिक कृषि कोऑपरेटिव सोसाइटी (पैक्स) हैं। इनमें कुछ तो काम नहीं कर रही लेकिन ज्यादातर सुचारू रूप से चल रही हैं। उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव के सदस्यों को ट्रस्टीशिप की भावना से काम करना चाहिए। कॉपरेटिव में रोजगार सृजन की क्षमता को देखते हुए इनकी छवि सुधारने की जरूरत है।

डॉ जोशी ने कॉपरेटिव के प्रति लोगों का नजरिया बदलने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि बार-बार रजिस्ट्रार के पास जाना अनुमति

लेना इन सब में काफी समय जाया होता है। उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी में चुनाव की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर जोर देते हुए कहा कि चुनाव आयोग को इसकी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इससे इन संस्थाओं में चुनाव को लेकर विवाद भी कम होंगे।

उन्होंने कहा कि नए मंत्रालय के गठन के बाद सहकारिता से जुड़े कानून में संशोधन के अनेक सुझाव आए हैं, लेकिन सहकार भारती का मानना है कि पहले राष्ट्रीय नीति तैयार की जानी चाहिए फिर उस नीति के आधार पर संशोधन किए जाने चाहिए। इससे आगे चलकर बार-बार बदलाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव में जरूरत के मुताबिक पूंजी निवेश नहीं हो रहा है। इनके लिए बांड, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर आदि के जरिए धन जुटाने के रास्ते तलाशने की जरूरत है। पैक्स में डिपॉजिट मोबिलाइजेशन की सुविधा है, इसे और बढ़ाया जाए तो यह और बेहतर तरीके से काम करेंगे।

डॉ जोशी ने सभी क्रेडिट सोसाइटी को डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज की जरूरत बताई। क्रेडिट सोसाइटी को काफी नकदी की हैंडलिंग करनी पड़ती है इसलिए उन्हें नेशनल पेमेंट सिस्टम में मेंबरशिप मिलनी चाहिए। इससे कैशलेस ट्रांजैक्शन को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि पैक्स ग्रामीण क्षेत्र में एफपीओ का काम कर सकते हैं। इसके लिए नियमों में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने के लिए पैक्स को मजबूत करना जरूरी है।

एनसीयूआई अपनी भूमिका निभाने में नाकाम: अजय वीर जाखड़

भारत कृषक समाज के चेयरमैन अजय वीर जाखड़ ने कोऑपरेटिव से जुड़े लोगों के प्रशिक्षण की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए एनसीयूआई का गठन किया गया लेकिन उसके काम को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है। ज्यादातर अधिकारी कोऑपरेटिव से जुड़े कानूनों से परिचित ही नहीं हैं। अधिकारी स्तर पर पारदर्शिता नहीं होती। इन परिस्थितियों को बदलना जरूरी है। जाखड़ ने कहा कि ज्यादातर कोऑपरेटिव नहीं चाहते कि वह अपने मुनाफे का हिस्सा एनसीयूआई के साथ साझा करें। कोऑपरेटिव क्षेत्र में सफलता के लिए जरूरी है कि उन कारणों को भी समझा जाए जिनकी वजह से कोऑपरेटिव विफल हुई हैं। उन्होंने कहा कि 1965 में भी कोऑपरेटिव में सुधार के लिए एक रिपोर्ट आई थी। उसमें जो मुद्दे बताए गए थे वह मुद्दे आज भी बरकरार हैं।

उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव सरकार की मदद के बिना नहीं चल सकते। लेकिन सरकारी मदद के साथ सरकार यानी राजनीतिक हस्तक्षेप भी बढ़ने लगता है। कोऑपरेटिव के कामकाज में हस्तक्षेप बढ़ने के कारण ही अब एफपीओ को तरजीह दी जाने लगी है। हालांकि एफपीओ के नियमों में भी कुछ समस्याएं हैं इसकी मुख्य वजह यह है कि नियम बनाते वक्त विदेशी सलाहकारों से बात की जाती है जो जमीनी हकीकत से वाकिफ नहीं होते।

भारत कृषक समाज और **असर** द्वारा, शुक्रवार, 17 जून 2022 को नई दिल्ली में "प
विषय पर आयोजित कार्य

सल अवशेष प्रबंधनः इस मौसम में प्रभाव के लिए क्या किया जा सकता है?''
ाला की सामुहिक तस्वीर।

जाखड़ ने कहा कि कोऑपरेटिव बैंकों को बड़े स्केल की जरूरत है। इसके बिना वे प्रतिस्पर्धी नहीं बन सकते। इसके लिए उन्होंने जिला कोऑपरेटिव बैंकों को राज्यस्तरीय बैंकों के साथ जोड़ने का सुझाव दिया। हालांकि उन्होंने पूंजी जुटाने के लिए डॉ जोशी के डिबेंचर और शेयर जारी करने के सुझाव पर असहमति जताई। उन्होंने यह भी कहा कि जो कोऑपरेटिव काम नहीं कर रही है उन्हें चुनाव प्रक्रिया से बाहर किया जाना चाहिए।

विशेषज्ञों ने दिए अन्य कई सुझाव

इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलायंस, एशिया-पैसिफिक के प्रेसिडेंट और कृभको के चेयरमैन डॉ. चंद्रपाल सिंह ने कहा कि बिना कोऑपरेटिव आंदोलन के देश को आर्थिक रूप से मजबूत नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि भारत में सहकारिता आंदोलन कृषि आधारित है। कृषि मजबूत हो तो सहकारिता भी मजबूत होगी। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलायंस (आईसीए) का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया की 12 फ़ीसदी आबादी कोऑपरेटिव से जुड़ी है। पूरे विश्व में 30 लाख के आसपास कोऑपरेटिव हैं। युवाओं को कोऑपरेटिव से जोड़ने के लिए उन्होंने उच्च शिक्षा में कोऑपरेटिव को एक विषय के तौर पर जोड़ने का सुझाव दिया। कोऑपरेटिव संस्थाओं को प्रोफेशनल तरीके से चलाने के लिए उन्होंने प्रशिक्षण की जरूरत बताई।

भारतीय रिजर्व बैंक के डायरेक्टर सतीश मराठे ने कहा कि कोऑपरेटिव को अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग में लाना होगा तभी उनका विकास हो सकता है। उन्होंने फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड्स के कोऑपरेटिव आंदोलन का अध्ययन करने का सुझाव दिया। कृषि क्षेत्र के लिए फ्रांस और नीदरलैंड तथा मैन्युफैक्चरिंग के लिए जर्मनी के मॉडल का अध्ययन किया जा सकता है। उन्होंने कोऑपरेटिव और बैंकिंग के बीच इंगेजमेंट बढ़ाने की जरूरत बताई। उन्होंने यह भी कहा कि कोऑपरेटिव के रोज का कामकाज देखने वाले मैनेजमेंट और उनकी ओनरशिप दोनों को अलग करना जरूरी है। सरकार के लिए उन्होंने सुझाव दिया कि वह रेगुलेशन तो करे लेकिन कोऑपरेटिव का माइक्रोमैनेजमेंट ना करे। उन्होंने कहा कि एग्रो प्रोसेसिंग के क्षेत्र में कॉपरेटिव के विकास की काफी संभावनाएं हैं।

खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के कोंडा रेड्डी चावा ने जापान, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड और फ्रांस के अध्ययनों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि डेनमार्क में कृषि कोऑपरेटिव उत्पादन से लेकर मार्केटिंग तक सब में सक्रिय है। भारत में भी किसानों को बड़े स्तर पर जोड़ने की जरूरत है। न्यूजीलैंड का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहां किसान कई बड़े बिजनेस और उद्योग संभाल रहे हैं।

इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलायंस, एशिया-पैसिफिक के सीईओ बालू अय्यर ने कहा कि सर्विस सेक्टर में कोऑपरेटिव के लिए अनेक संभावनाएं हो सकती हैं।

उन्होंने कहा कि देश की जीडीपी में सर्विस सेक्टर का योगदान 50 फ़ीसदी से अधिक है लेकिन इसका बड़ा हिस्सा असंगठित है। अमेरिका का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहां सफाई कर्मियों ने मिलकर कोऑपरेटिव खड़ा किया है। इसके सदस्यों को निजी कंपनी की तुलना में अधिक आमदनी होती है। इसके अलावा कोऑपरेटिव को जो मुनाफा होता है उसमें उनकी हिस्सेदारी भी होती है। अय्यर ने भी कोऑपरेटिव के लिए पूंजीं जुटाने के तरीकों पर विचार करने की बात कही।

इरमा के डॉ. शाश्वत विश्वास ने कोऑपरेटिव के कामकाज में पेशेवर तौर तरीके अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव के साथ निजी क्षेत्र को भी सरकार की मदद की जरूरत पड़ती है लेकिन सरकार निजी कंपनियों के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करती जबकि कोऑपरेटिव के काम में उसका हस्तक्षेप होता है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर कोऑपरेटिव आज भी बहुत पुराने तौर तरीके से चल रहे हैं। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से उनके कामकाज में पारदर्शिता लाई जा सकती है। उन्होंने कोऑपरेटिव के गवर्नेंस में सुधार पर भी जोर दिया।

एनएफसीएसएफ लिमिटेड के एमडी प्रकाश नायकनवरे ने विभिन्न क्षेत्रों में कोऑपरेटिव की अहमियत बताते हुए कहा कि महाराष्ट्र की शुगर कोऑपरेटिव मिल चलाने के साथ अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, शिक्षण संस्थान, कंज्यूमर स्टोर, कॉपरेटिव बैंक सब कुछ चला रहे हैं। ऐसा दूसरी जगहों और दूसरे क्षेत्रों में भी हो सकता है। उन्होंने भी कॉपरेटिव के कामकाज में प्रोफेशनलिज्म की कमी का मुद्दा उठाया और कहा कि प्रशिक्षण तथा टेक्नोलॉजी के जरिए इसे दूर किया जा सकता है। उन्होंने शुगर कोऑपरेटिव को दीर्घकालिक लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि कॉपरेटिव को अपनी मार्केटिंग पर भी ध्यान देना चाहिए जो अभी वे नहीं करते हैं।

नैकॉफ चेयरमैन राम इकबाल सिंह ने कहा कि इस कार्यक्रम में जो सुझाव दिए जा रहे हैं उन पर सरकार को अमल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि छोटे किसानों के लिए सरकारी अधिकारियों के पास जाना और अपनी बात कह पाना मुश्किल होता है। इसलिए कॉपरेटिव के नियम आसान होने चाहिए। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय संगठनों की भूमिका पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव का कोई विकल्प नहीं है।

सहकार भारती के प्रेसिडेंट डॉ डीएन ठाकुर ने कहा कि कोऑपरेटिव ना कभी अप्रासंगिक हुए और ना कभी हो सकते हैं। चाहे खाद्य सुरक्षा हो, ऊर्जा की सुरक्षा हो या सामाजिक सामंजस्य यह सब कोऑपरेटिव के जरिए ही सुनिश्चित हो सकता है। अभी तक कोई भी कोऑपरेटिव अंदरूनी कारणों से नहीं बल्कि बाहरी तत्वों के कारण विफल हुआ है। कोऑपरेटिव की तुलना प्रकृति से करते हुए उन्होंने कहा की प्रकृति की तरह इसमें भी संतुलन जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव का कोई विकल्प नहीं है। इसके बिना समस्या बढ़ेगी। कोऑपरेटिव को प्रासंगिक बनाने के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण और जागरूकता जरूरी है।

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

RNI No. 831/1957 प्रकाशन की तिथि : 1 जुलाई, 2022
पोस्टल रजि० DL (S)-01/3092/2021-23 एल.पी.सी., दिल्ली आर.एम.एस, दिल्ली–6,
पहले भुगतान किये बिना पोस्ट करने का लाइसेंस नं. तारीख 4 एवं 5, जुलाई 2022
U(C)-92/2021-23

सार्वजनिक सूचना

भारत कृषक समाज के सदस्यों से अनुरोध है कि वे भारत कृषक समाज के महासचिव के कार्यालय के साथ अपने संपर्क विवरण को अद्यतन करें।

संपर्क विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है:

नामः _____

सदस्यता संख्याः _____

वर्तमान पताः _____

_____

टेलीफोन नंबरः _____

मोबाइल नंबरः _____

ईमेलः _____

(कृपया पते का सबूत की एक छायाप्रति संलग्न करें)

विधिवत भरा हुआ फॉर्म निम्नलिखित पते पर स्पीड पोस्ट या ईमेल द्वारा इस माह के अन्त तक या उससे पहले जमा कराएं:

महासचिव
भारत कृषक समाज
ए–1, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली, 110013
ईमेलः– Samdarshi.bks@gmail.com
टेलीफोनः– 011–41402278

नोटः आपसे अनुरोध है कि आप अन्य सदस्यों को भी ऐसा करने के लिए सूचित करे।

भारत कृषक समाज ए–1, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली– 110013, फोनः 011–41402278, 9667673186, ई–मेलः ho@bks.org.in, **वैबसाईटः** www.bks.org.in **के लिए श्री उरविन्द्र सिंह भाटिया द्वारा सम्पादित, मुद्रित व प्रकाशित तथा एवरेस्ट प्रेस, ई 49/8 ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेस –2, नई दिल्ली –110020 द्वारा मुद्रित।**